भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

1623. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधाकिशन मालवीय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या "अग्नि" और अन्य प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान और चीन द्वारा तैनात किए गए प्रक्षेपास्त्रों की तुलना में अधिक कारगार साबित होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : "अग्नि" केवल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रक्षेपास्त्र है जो इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सुविज्ञता और पुनप्रवेक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रमाण है । देश में ही विकसित किए जा रहे "पृथ्वी", "आकाश", "त्रिशूल" तथा "नाग" प्रक्षेपास्त्र किसी अन्य देश के इस श्रेणी के इस समय के प्रक्षेपास्त्रों के मुकाबले के होंगे ।

भोपाल में दूरदर्शन केन्द्र का प्रारंभ न किया जाना

1624. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधाकिशन मालवीय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सम्पूर्ण तैयारी हो जाने के बाद भी, केवल शिथिलता के कारण भोपाल का दूरदर्शन केन्द्र प्रारम्भ नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ;

(ग) इसका कार्य प्रारम्भ करते समय विभाग की इसे कितने समय में चालू कर देने की योजना थी; और इसके प्रारम्भ किए जाने की लागत और समय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या उपरोक्त केन्द्र के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है और वे वहां तैनात भी किये जा चुके हैं परन्तु वे बेकार बैठे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :(क) से (ग) शुरू में भोपाल दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र की स्थापना की परियोजना को जून 1990 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था । तथापि परियोजना स्थल पर आने वाली कई कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप इस पर लगभग 18 महीने का अधिक समय लग गया । परियोजना लागत भी बढ़ गई । लेकिन यह समूची वृद्धि सीधे अधिक समय लगने से संबंधित नहीं है ।

वर्तमान संकेतों के अनुसार अब इस परियोजना को चालू वर्ष के अंत तक सेवा के लिये शुरू किये जाने का कार्यक्रम है ।

(घ) केन्द्र के लिए पूरे स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है और कुछ पद भी भर लिये गये हैं । जो कार्मिक ड्यूटी पर हाजिर हो गए हैं, उन्हें प्रारम्भिक कार्य पर लगा दिया गया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास

1625. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यय किए जाने का उपबंध करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र इस समय इस प्रयोजन के लिए कितना प्रतिशत व्यय कर रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा